भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1468 का उत्तर

श्रीशैलम तीर्थस्थल हेतु कनेक्टिविटी

1468. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल श्रीशैलम के लिए रेल कनेक्टिविटी में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या श्रीशैलम तक पहुंच बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रेल लाइनों अथवा स्टेशनों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी पहलें शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्रीशैलम तीर्थस्थल हेतु कनेक्टिविटी के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में डॉ. बायरेड्डी शबरी के अतारांकित प्रश्न सं. 1468 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं की स्वीकृति और निष्पादन राज्य-वार/शहर-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

हैदराबाद (तिम्मापूर)-श्रीशैलम (103.60 किमी) और मार्कापुर रोड-श्रीशैलम (56 किमी) के बीच नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किए गए थे। बहरहाल, कम यातायात संभाव्यता के कारण परियोजना के आगे का कार्य नहीं किया जा सका। भारतीय रेल पर रेल परियोजनाओं को स्वीकृति देना सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक्स और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, तीर्थ स्थलों तक संपर्क सहित सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों आदि पर निर्भर करता है।

निधि आवंटन और भारतीय रेल में तद्नुरूप परियोजनाओं को कमीशन करने में काफी वृद्धि हुई है। तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:-

वर्ष	बजट परिव्यय
2023-2024	4,418 करोड़ रुपए
2024-2025	5,336 करोड़ रुपए

तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: स्थित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को कमीशन करने की स्थिति इस प्रकार है:-

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमिशन की गई औसत लंबाई	2009-14 के दौरान औसत कमिशनिंग की तुलना में परिवर्तन
2009-14	87 किलोमीटर	17.4 किमी. प्रतिवर्ष	-
2014-24	650 किलोमीटर	65 किमी. प्रतिवर्ष	3.7 गुना से अधिक

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना/निष्पादन होना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु की परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और यह सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

*****